

असधारण

EXTRAORDINARY

भाग **II - जण्ड** 3—उपसम्ब (i)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

સં∘ 169] No. 169] नई दिल्ली, पृहस्पतिबार, जून 22, 1972/प्रापाद 1, 1894 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 22, 1972/ASADHA 1, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compliation

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June 1972

Monopolies and Restrictive Trade Practices (Third Amendment) Rules, 1972

- G.S.R., 321(E),—In exercise of the powers conferred by Section 67, of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Monopolies and Restrictive Trade Practices (Third Amendment), Rules, 1972.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In rule 4A of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970 (hereinafter referred to as the said rules), after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
 - "(5) Notwithstanding anything contained in this rule, if the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do in the interests of the defence of India, security of the State or in the public interest, it may, by a general or special order, dispense with the publication of the general notice referred to in sub-rule (1) in respect of any undertaking or class of undertakings or in respect of any goods or services."

3. In rule 5 of the said rules, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

- "(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do in the interests of the defence of India, security of the State or in the public interest, it may, by a general or special order, specify any other form of notice to be given under sub-section (1) of section 21 of the Act in respect of any undertaking or class of undertakings or in respect of any goods or services."
- 4. In rule 6 of the said rules, after sub-rule (2), the following sub-rule shall $\mathbf{b}_{\mathcal{C}}$ inserted, namely:—
 - "(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do in the interests of the defence of India, security of the State or in the public interest, it may, by a general or special order, specify any other form of application to be made under sub-section (2) of section 22 of the Act in respect of any undertaking or class of undertakings or in respect of any goods or services."

[No. 4/1/72-M.II.]

C. R. D. MENON, Under Secy.

कल्पनी कार्य विभाग

श्रधिसचना

नई दिल्ली, 22 जून, 1972

एकाधिकार तथा अवरीधक व्यापारिक व्यवहार (तृतीय संशोधन) नियम, 1972

सावकाविक 321 (भ).—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार प्रधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त णिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एकाधिकार तथा प्रवरोधक व्यापारक व्यवहार नियम, 1970 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्मलिखित नियम एतद्वारा बनाती है, अर्थात : ——

- (1) इन नियमीं का नाम एकाधिकार तथा प्रवरीधक व्यापारिक व्यवहार (तृतीय संशोधन) नियम, 1972 होगा ।
 - (2) ये राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख को प्रकृत होंगे।
- 2. एकाधिकार तथा भ्रवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4क में, उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम ग्रन्तः स्थापित किया जाएगा, श्रर्थात् :---
 - "(5) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा के हितों में या लोक हित में ऐसा करना ग्रावण्यक या समीचीन है, वह किसी साधारण या विशेष ग्रादेश द्वारा, किसी उपक्रम या उपक्रमों के वर्ग के बारे में या किमी माल या सेवाश्रों के बारे में उपनियम (1) में निर्दिष्ट साधारण सूचना के प्रकाणन से ग्रभिमक्त कर सकेगी)।

- 3. उक्त नियम के नियम 5 में, ्रेडवनियम (4) के पण्वात् निम्नलिखित उपनियम श्रन्तः स्थापित किया जाएगा, श्रर्थात् ः—
 - "(5) उपनियम (1) में किमी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा के हितों में या , लोक हित में एसा करना आवश्यक या समीचीन है, बह, किसी साधारण या विशेष प्रादेग हारा, किसी उपक्रम या उपक्रमों के वर्ग के बारे में या किसी माल या सेवाफ्रों के के जारे में अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन दी जाने वाली सचना का कोई अन्ध्यामुक्य विनिधिष्ट कर सकेगी।"
- 4. उक्त नियम 6 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित पुरितयम श्रन्तःस्थापिन किया जाएगा श्रथति :—ी
 - "(3) उपनियम (1) में किसी बात क होत हुए, भी, यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि भारत की रक्षा, राज्य की मुरक्षा के हितों में या लौक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह किसी माधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी उपक्रम या उपक्रमों के वर्ग के वारे में या किसी माल या सेवाओं के बारे में, अधिनियम की धारा 22 की उपप्रारा (2) के अधीन किए जाने वाल आवदन के किसी अन्य प्रारूप को विनिर्दिष्ट कर मुनकेगी।"

[सं० 4/1/72 **-ए**म Π] सी०ग्रार०डी० $^{2}_{1}$ मैं नन, ग्रवर सचिव।